



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

अधि II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]
No. 77]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 1987/माघ 24, 1908
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 1987/MAGHA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 94 (अ) —केन्द्रीय सरकार, महापत्तन
न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा
132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
एतद्वारा कलकत्ता पत्तन (हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स) के
लिए न्यासी मडल द्वारा निर्मित और इस अधिसूचना के
साथ सलग्न अनुसूची में उल्लिखित कलकत्ता न्यास (हल्दिया
डॉक काम्प्लेक्स (कर्मचारी कल्याण निधि) विनियम, 1987
का अनुमोदित प्रदान करती है ।

2 ये विनियम इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र
में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवक्त होंगे ।

[फा. स. पी. डब्ल्यू./पी. ई. आर. 22/85]
योगेन्द्र नारायण, सयुक्त सचिव

अनुसूची

कलकत्ता पत्तन न्यास (हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स)
कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1987

मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 (1963 का 38)
की धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए
एवं इस विषय पर वर्तमान नियमों का अधिकरण करते हुए
कलकत्ता पोर्ट का न्यासी मडल एतद्वारा निम्नलिखित
विनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :—(1) ये विनियम
कलकत्ता पत्तन न्यास (हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स) कर्मचारी
(कल्याण निधि) विनियम 1987 कहें जा सकेंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन विनियमों में जब तक प्रसंग
से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) “अधिनियम” से मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट अभिप्रेत
होगा ।

(ख) “उपाध्यक्ष” का वही अर्थ होगा जो कि अधि-
नियम में निर्दिष्ट है ।

(ग) "उप महाप्रबंधक" "उप प्रबंधक (वित्त)" व "प्रबंधक (का. व औ. सम्प.)" से उपर्युक्त पदों के पदस्थ से अभिप्रेत है जिन्हें अधिनियम की धारा 24 के तहत नियुक्त किया गया है।

(घ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत हल्दिया डाक कमप्लेक्स के अन्तर्गत कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के किसी भी पद या रूप से कार्य करने वाले कर्मचारी से है जिसमें कारीगर, तथा अन्य मासिक वेतन भोगी कर्मचारी या तो कुशल या अकुशल शामिल हों तथा जिसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विदेश सेवा पर हो या जिसकी सेवा अस्थायी रूप से बोर्ड के अधिकार में हो या कोई भी व्यक्ति जोकि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकार की सेवा में हों, जिनकी सेवाएं अस्थायी रूप से बोर्ड के अधिकार में है, भी शामिल है। यह इसमें निर्धारित सीमा तक जिसमें यथा परिभाषित कर्मचारियों के परिवार तथा आश्रित भी शामिल है इसमें निलम्बित कर्मचारियों को किसी भी तरह शामिल नहीं किया जायेगा।

(ङ) "परिवार से अभिप्रेत कर्मचारी की पत्नी या पति, माता-पिता व धर्मज बच्चा एवं सौतेला बच्चा जोकि कर्मचारी के साथ स्थायी रूप से रहता है तथा उस पर पूर्ण रूप से आश्रित है। इस खंड के प्रयोजन के लिए स्पष्टिकरण :-

(1) बच्चों से अभिप्रेत उन लड़कों से है जिनकी उम्र 21 साल हो तथा कुंवारा एवं विधवा लड़कियों परन्तु लड़के एवं कुंवारे तथा विधवा लड़कियां जोकि आकस्मिक आधार से अन्यथा पर नियुक्त है तथा 250/-रु. से अधिक प्रतिमाह वेतन पाते हैं, उन्हें कर्मचारी का पूर्ण आश्रित नहीं कहा जायेगा।

(2) कर्मचारी के माता-पिता, जिसमें सौतेला बाप तथा सौतेली मां शामिल है, को कर्मचारी का पूर्ण आश्रित समझा जायेगा यदि उनके विभिन्न स्त्रोतों से होने वाली आबर्ती मासिक आय 250/- रु. प्रतिमाह से अधिक न हो। हर वित्तीय वर्ष के आरम्भ में एकबार संबंधित कर्मचारी को अपने माता-पिता की आय के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा।

(च) "आश्रित" से अभिप्रेत होगा कर्मचारी की पत्नी या पति, माता-पिता, धर्मज बच्चें इत्यादि जोकि कर्मचारी के साथ स्थायी रूप से रहते हैं तथा उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं जसा कि ऊपर (घ) में निदिष्ट है।

(छ) "शासी निकाय" से अभिप्रेत कल्याण निधि के शासी निकाय से होगा।

(ज) "कल्याण निधि" से अभिप्रेत होगा "कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट (हल्दिया डाक कमप्लेक्स) कर्मचारी कल्याण निधि" जोकि विनियम (3) के उप विनियम (क) के अन्तर्गत स्थापित है।

3. कल्याण निधि का संविधान एवं व्यवस्था।

(क) हल्दिया डाक कामप्लेक्स से कर्मचारियों के हित के लिए बोर्ड द्वारा एक निधि का निर्माण किया जायेगा जिसे कल्याण निधि कहा जायेगा।

(ख) कल्याण निधि की व्यवस्था एवं संचालन शासी निकाय द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

- (1) उपाध्यक्ष
- (2) उप महाप्रबंधक
- (3) उप प्रबंधक (वित्त)
- (4) प्रबंधक (का. व औ. सम्प.)

(ग) उपाध्यक्ष एवं उनकी अनुपस्थिति में उपमहाप्रबंधक शासी निकाय के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(घ) शासी निकाय की बैठक ऐसे अन्तराल पर एवं ऐसे समय पर तथा स्थान पर हो जसा कि उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपमहाप्रबंधक निदेश दें।

(ङ) शासी निकाय की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा तथा बैठक के अध्यक्ष द्वारा इसे अधिप्रमाणित किया जायेगा।

4. कल्याण निधि का वितरण

निम्नलिखित स्त्रोतों से उत्पन्न धन बोर्ड द्वारा भुगतान के रूप में कल्याण निधि में जमा किया जायेगा :—

(क) बोर्ड के सामान्य राजस्व से अंशदान जैसा कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा मंजूर किया जाये बशर्ते कि अधिकतम सीमा एक लाख सालाना हो ;

(ख) वेतन, मजदूरी भत्ते एवं किसी भी प्रकार का अन्य जमा फंडरी में नियुक्त कर्मचारी से भिन्न जैसा कि फंडरी ऐक्ट 1948 की धारा 2 (एम) में परिभाषित है, किसी कर्मचारी द्वारा मांगी न गयी हो या ऐसे कर्मचारी की ओर से कोई भी उम तिथि से जिस पर वेतन, मजदूरी भत्ते तथा अन्य जमा संबंधित कर्मचारी को देय हों से तीन साल छह महीने की समाप्ति के बाद जमा राशि।

परन्तु यदि बोर्ड तीन साल छह महीना बीतने के बाद भी दावे का पूर्वाधिकार मान नेता है तो उक्त रकम कल्याण निधि में से दिया जायेगा।

(ग) फैक्टरी में नियुक्त कर्मचारियों से भिन्न, जैसा कि फैक्टरी ऐक्ट, 1948 की धारा 2 (एम) में परिभाषित है, कर्मचारियों से प्राप्त सभी जुमाने।

(घ) कल्याण निधि पर ब्याज द्वारा प्राप्त सभी प्रकार की राशि।

5. कल्याण निधि का निवेश :

कल्याण निधि के शुद्ध परिचालन अधिशेष का निवेश केन्द्रीय सरकार में या राज्य सरकार के किसी प्रतिभूति में या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ऋणपत्रों या अन्य न्यासी प्रतिभूतियों जिसके ब्याज एवं पूंजी के भुगतान के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गारन्टी दिया गया हो या स्टेट बैंक आफ इंडिया में आवधिक जमा या अन्य राष्ट्रीय या अनुसूचित बैंक जैसा कि शासी निकाय समय-समय पर निर्धारित करे, किया जायगा।

6. कल्याण निधि के कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्य :

शासी निकाय कल्याण निधि का प्रयोग ऐसी कार्य-वाहियों से संबंधित खर्चों के लिए करेगा जिसे बोर्ड समय-समय पर कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल है, अर्थात् :—

- (1) कर्मचारियों तथा उनके परिवार के कल्याण से संबंधित संस्थानों, क्लबों, सहकारी समितियों तथा अन्य सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए दान, चन्दा तथा उसी प्रकार से ;
- (2) कर्मचारियों द्वारा संचालित सहकारी समितियों को ब्याज के ऐसे समुचित दर पर जैसा कि समय-समय पर शासी निकाय निर्धारित करे, ऋण की स्वीकृति;
- (3) कर्मचारियों तथा उनके आश्रित बच्चों के लिए शैक्षणित सुविधाएं (वाचनालय एवं पुस्तकालय सहित)।
- (4) कर्मचारियों पर लागू मेडिकल अटेंडेंट फ़ेस में न पड़ने वाली चिकित्सा के लिए चिकित्सा सहायता तथा स्वास्थ्य लाभ केन्द्र खर्चा;
- (5) कर्मचारियों के खेल-कूद और मनोरंजन के लिए मंजूरी;
- (6) कर्मचारियों को जीवन रक्षा तथा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेष पुरस्कार का भुगतान;
- (7) शोर संकट में कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता ;

(8) इयूटी में जाते समय या लौटते समय या काम करते समय यदि कोई कर्मचारी मर जाय या गंभीर रूप से घायल हो जाय तो ऐसे कर्मचारी के परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता दिया जाना ;

(9) कर्मचारियों तथा उनके परिवारवालों की भलाई के लिए किसी अन्य प्रकार के खर्च को उपाध्यक्ष अपने विवेक से स्वीकार कर सकते हैं।

7. कल्याण निधि से भुगतान :

कल्याण निधि से किसी प्रकार के भुगतान के लिए उपाध्यक्ष से या उनकी अनुपस्थिति में “उप महाप्रबंधक से मंजूरी लेनी होगी लेकिन इन भुगतानों को शासी निकाय की अगली बैठक में शासी निकाय के सामने प्रस्तुत किया जाय।

आगे शर्त यह है कि 250/- रु. से अधिक के भुगतान के लिए शासी निकाय की मंजूरी आवश्यक होगी।

8. कल्याण निधि का संचयन :

- (1) कल्याण निधि में संचित राशि दो लाख से अधिक नहीं होगी।
- (2) उप विनियम (1) में निर्धारित अधिकतम राशि से अधिक राशि को बोर्ड के राजस्व लेखे में जमा करना होगा।

9. कल्याण निधि के लिए अलग वित्तीय लेखा रहेगा।

10. बोर्ड को इन विनियमों के संशोधन या उसमें जोड़ने का अधिकार है बोर्ड जब उपयुक्त और समीचीन समझे।

11. इन विनियमों की व्याख्या तथा कार्यों से संबंधित प्रश्नों में उपाध्यक्ष का निर्णय अंतिम तथा निर्णायक होगा।

12. निरसन व बचत :

- (1) इन विनियमों के प्रारम्भ होने पर प्रत्येक नियम, विनियमों, संकल्प या आदेश जो लागू हैं, प्रारम्भ के तुरंत बाद, जहां तक कि इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी विषय के लिए इसमें व्यवस्था हो, खालू नहीं रहेंगे।
- (2) ऐसे संचालन की समाप्ति के बावजूद, पूर्व नियम, विनियम, संकल्प या आदेश के अन्तर्गत की गयी किसी चीज या किसी कार्रवाई को इन विनियमों की व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया समझा जायगा।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 13th February, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 94(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 read with sub-section (1), of Section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust (Haldia Dock Complex) Employees' (Welfare Fund) Regulations, 1987, made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta (HDC) and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[File No. PW/PER-22/85]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

THE CALCUTTA PORT TRUST (HALDIA DOCK COMPLEX) EMPLOYEES' (WELFARE FUND)

REGULATIONS, 1987

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the existing rules on this subject the Board of Trustees of the Port of Calcutta hereby makes the following Regulations :—

1. Short title and commencement.—These Regulations may be called the Calcutta Port Trust (Haldia Dock Complex) Employees' (Welfare Fund) Regulations, 1987.

2. Definitions.—In these Regulations unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" shall mean the Major Port Trust Act, 1963.
- (b) "Deputy Chairman" shall have the same meaning as assigned to it in the Act.
- (c) "Deputy General Manager", "Deputy Manager (Finance)" and "Manager (P&IR)" shall mean the incumbents of the said posts, appointed under Section 24 of the Act.
- (d) "Employee" shall mean an employee of the Calcutta Port Trust under the Haldia Dock Complex in any post or capacity and shall include artisans, and other monthly rated employees whether skilled or unskilled and shall also include any such persons on foreign service or whose service are temporarily placed at the disposal of the Board and also any person in the service of the Central or State Government or a local or other authority whose services are temporarily placed at the disposal of the Board. It shall also to the extent prescribed herein include the families and dependents of the employees as defined. It shall not, however, include employees under suspension.
- (e) "Family" shall mean wife or husband, parents and legitimate children including legally adopted children including legally adopted children and step-children, permanently residing with and wholly dependent on the employee. Explanation for the purposes of this clause :—
- (i) "Children" means sons not over the age of 21 and unmarried and widowed daughters provided that sons and unmarried and widowed daughters who are employed otherwise than on casual basis and drawing a salary of more than Rs. 250 per

month shall not be regarded as wholly dependent on an employee.

- (ii) The parents including step-father and step-mother shall be regarded as "wholly dependent" on an employee if their total recurring monthly income from all sources does not exceed Rs. 250. The declaration regarding the income of parents shall be furnished by the employee concerned once in the beginning of each financial year.
- (f) "Dependent" shall mean wife or husband, parents and legitimate children, etc. who are permanently residing with and wholly dependent on the employee as indicated vide (d) above.
- (g) "Governing Body" shall mean the Governing Body of the Welfare Fund.
- (h) "Welfare Fund" means the "Calcutta Port Trust (Haldia Dock Complex) Employees' Welfare Fund" established under Sub-Regulation (a) of Regulation (3).

3. Constitution and Management of Welfare Fund :

- (a) There shall be constituted by the Board a Fund to be called the Welfare Fund for the benefit of the employees of the Haldia Dock Complex.
- (b) The management and the control of the Welfare Fund shall vest in a Governing Body consisting of—
 - (i) the Deputy Chairman.
 - (ii) the Deputy General Manager.
 - (iii) the Deputy Manager (Finance).
 - (iv) the Manager (P&IR).
- (c) The Deputy Chairman and in his absence, the Deputy General Manager shall be ex-officio Chairman of the Governing Body.
- (d) The Governing Body shall meet at such intervals and at such time and place as the Deputy Chairman or in his absence, the Deputy General Manager may direct.
- (e) The proceedings of the Governing Body shall be recorded in a Minutes Book and shall be authenticated by the person presiding at the meeting.

4. Contribution to Welfare Fund.—All money accruing from the following sources shall be credited to the Welfare Fund by way of payment by the Board :—

- (a) the contributions from the general revenues of the Board as may be sanctioned by the Board from time to time subject to the maximum limit of one lakh rupees per annum ;
- (b) the salaries, wages, allowances and other dues of any kind whatsoever not claimed by any employee other than the employees employed in a "factory" as defined in Section 2(M) of the Factories Act, 1948 or anybody on behalf of such employee, after the expiry of three years and six months from the date on which salaries, wages, allowances and other dues became due to the employee concerned.

Provided that if the Board accepts the claim preferred after the expiry of the period of three years and six months the said amount shall be paid out of and debited to the Welfare Fund ;

- (c) All fines realised from employees other than the employees employed in a "factory" as defined in Section 2(M) of the Factories Act, 1948 ;
- (d) all sums of money that may accrue to the Welfare Fund by way of interest,

5. Investment of Welfare Fund.—The net operating surplus of the Welfare Fund shall be invested in the Central Government or any State Government Securities or the Calcutta Port Trust Debentures or other Trust Securities guaranteed by the Central Government or State Government in respect of payment of interest and capital or in fixed deposit with the State Bank of India or other nationalised or scheduled Bank as the Governing Body may from time to time decide.

6. Scope and objects of the Welfare Fund.—The Welfare Fund shall be utilised by the Governing Body to meet any expenditure incurred in connection with such measures as may be specified by the Board from time to time to promote the welfare of employees and may include the following, namely:—

- (i) Donations, subscriptions and the like to institutes, clubs, co-operative societies or other similar objects connected with the welfare of the employees and their families;
- (ii) grant of loan to co-operative societies, organised by the employees, at such reasonable rate of interest as may be determined by the Governing Body from time to time;
- (iii) educational facilities (including reading rooms and libraries) for employees and their dependent children;
- (iv) medical relief, not covered by the Medical Attendant Rules applicable to the employees, and convalescent homes expenses;
- (v) grant for sports, excursions and entertainments for the employees;
- (vi) payment of any special rewards to employees for life saving or other meritorious acts;
- (vii) financial assistance, to the employees and their dependents in acute distress;
- (viii) rendering immediate financial relief to the families of the employees who die or sustain serious injuries while on duty or while going to or returning from duty;

- (ix) any other item of expenditure for the benefit of the employees and their families at the discretion of the Deputy Chairman.

7. Payment from Welfare Fund.—Any payment from the Welfare Fund shall be sanctioned by the Deputy Chairman, or in his absence, by the Deputy General Manager provided such payments are reported to the Governing Body at their next meeting:

Provided further that a payment exceeding two hundred and fifty rupees shall require the sanction of the Governing Body.

8. Accumulation of Welfare Fund:

- (i) The maximum amount that may be held in the Welfare Fund shall not exceed rupees two lakhs.
- (ii) Any sum in excess of the maximum specified in sub-Regulation (i) shall be credited to the Board's Revenue Account.

9. There shall be separate financial accounts for the Welfare Fund.

10. The Board reserves the right to add to or amend these regulations as and when it thinks fit and proper.

11. In all questions of interpretation or working of these Regulations, the decision of the Deputy Chairman shall be final and conclusive.

12. Repeal and Savings:

- (i) On the commencement of these regulations every rule, regulations, resolution or order in force immediately before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these regulations, cease to operate.
- (ii) Notwithstanding such cessation of operation, anything done or any action taken under any previous rule, regulation, resolution or order shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these regulations.

